vk'kk QVdj e ,Q-Mh-vkb- d fojk/k e D;k g\

भारत सरकार ने 24 नवम्बर 2011 को कई ब्रान्डों के फुटकर में एफ.डी.आई. से संबंधित अपनी नीति की घोषणा की थी, जिसमें कई ब्रांड्स के फुटकर बाजार और एकल ब्रांड बाजार में 100 प्रतिशत एफ. डी.आई. के लिये ''घरेलू हितग्राहियों के लिये पर्याप्त सुरक्षा के विषय में'' सरकारी स्वीकृति के माध्यम से 51 प्रतिशत तक के विदेशी शेयर को अनुमति दी गई। इसका समर्थन आगे यह कहकर भी किया गया कि यह नीति केवल उन शहरों के लिये होगी जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है (जिसका मतलब है 53 शहर 2011 जनगणना के अनुसार)। न्यूनतम नियत निवेश 100 मिलियन डॉलर है, जिसमें आधी राशि का निवेश बैक–एंड अवसंरचना में किया जाना है (कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेशन, यातायात, पैकिंग, वर्गीकरण, संसाधन आदि)। सरकार का यह मानना है कि इससे फसल के बाद के नुकसान कम होंगे और किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे। जब इस नीति की घोषण की गई तो इसमें 1 मिलियन डॉलर से कम के प्रमुख निवेश के साथ सूक्ष्म और छोटे भारतीय उद्योगों के न्यूनतम 30 प्रतिशत के स्रोत को आवश्यक रखा गया। सरकार ने इसे यह कहकर उचित ठहराया है कि इससे 'घरेलू मूल्य में वृद्धि और निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार, तकनीकी उन्नतिकरण और आय निर्माण में भी वृद्धि होगी।'

चूंकि इस नोट को लिखते समय, यू.पी.ए. सरकार के सहयोगियों सहित इन प्रस्तावों का कई जगहों से विरोध किया गया, इसलिये सरकार ने इस नीति के निलम्बन की घोषणा कर दी। फिर भी, आशा यह विश्वास करता है कि इस बहस को आगे बढ़ाते रहना उचित होगा, क्योंकि इन प्रस्तावों को फिर से वापस लाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि किसी भी स्थान के अनुभवों और वर्तमान भारतीय वास्तविकता (गरीबी और भूख के बड़े गिराव, ज्यादातर किसानों का लघुधारक होना आदि) के आधार पर इसे स्पष्ट किया जाए, कि इस प्रकार के प्रस्ताव में बताए गए भारतीय किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिये स्टोर के क्या हालात हैं और क्यों उन्हें इन्हें अस्वीकार करना चाहिये।

vk'kk ns'k d y?kq/kkjdk ij fo'ks"k /;ku nsrs g, nh?kdkfyd d`f"k ij viu [kn d /;ku vkj nf'Vdk.k l QVdj iLrko e ,Q-Mh-vkb- ij utj j[krk gA bldk n<rk l ;g ekuuk g fd cMh fons'kh QVdj ndkuk l fdlku vkj miHkkDrk nkuk cnh cu tk;x vkj yk[kk dh vkthfodk ij cjk vlj iMxkA dbZ vU; uhfr;k dh rjg] bld my>ko vkj iHkko e/;e dky vkj nh?k dky e fn[kkbZ nuk "k: gkxA bld vykok] cMs gh /;ku l fd;k x;k ,d fo'y"k.k ;g crkrk g fd ljdkj d ;s dne Hkkjrh; vFkO;oLFk d ykHk e ugh g] cfYd fdlh vkj LFkku d vlQy vkfFkd <kp dk lgk;rk nu d fy;s gA bldh "k:vkr d ifj.kkeLo:i Hkkjr l iSlk ckgj tk,xk u fd Hkkjr e vk, tSlk fd iLrkfor fd;k tk jgk gA tSlk fd dbZ vU; uhfr;k vkj fo/kkuk d dsl e gvk g] ;g LokHkkfod g fd ljdkj ogn Lrj ij gk jgh lkoZtfud cgl e ie[k ennk dk ugh [kky jgh g vkj ,d rjQk fu.k;; ydj i{kikr dj jgh gA ;g gekjh ykdrkf=d 0;oLFkk d fy;s vPNk ugh gA

लेकिन सबसे पहले, कुछ तथ्य और आंकड़ें:

भारत का खुदरा व्यापार अनुमानतः 400–450 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से 95 प्रतिशत पारंपरिक दुकानदारों के हाथों में है। 63 प्रतिशत कृषि व्यापार फुटकर हाथों में है। यह प्रतिवेदित किया जाता है कि लगभग 7 लाख गांवों के 58.8 मिलियन लघुधारक अपने बनाए उत्पादों को लगभग 15 मिलियन व्यापारियों (थोक और फुटकर विक्रेता) को बेचते हैं। आगे यह भी बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर

For more information, contact: Kavitha Kuruganti, Convenor, at kavitha.kuruganti@gmail.com

अपने उत्पादकों से 16 कि.मी. के व्यास के अंदर ही रहते हैं। भारतीय खुदरा बाजार के 2020 तक 1250 बिलियन डॉलर तक के बढ़ने की संभावना है।

वॉलमार्ट, जिसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, का वार्षिक बिक्री 400 बिलियन डॉलर या 18 लाख करोड़ रुपये है; कैरेफोरः 130 बिलियन डॉलर; टेस्कोः 100 बिलियन डॉलर; मेट्रोः 96 बिलियन डॉलर। इन कम्पनियों की सालाना बिक्री के परिमाण का अनुमान प्रदान करने के लिये, वॉलमार्ट की 18 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक बिक्री की तुलना इससे करते हैंः भारतीय केन्द्र सरकार का 2011–12 के बजट में 12.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया गया। इन बड़े विक्रेताओं का मार्केट शेयर अलग–अलग देशों में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से ऊपर तक हैं! ऐसी एकाग्रता और प्रभुत्व भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है। वर्तमान स्थिति का अर्थ है उपभोक्ताओं, किसानों और वितरकों को ज्यादा लाभ।

400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वार्षिक बिक्री वाले वॉलमार्ट में मात्र 2.1 मिलियन लोगों को रोजगार दिया गया है, और यह वर्तमान भारतीय फुटकर बाजार के रोजगार के 5 प्रतिशत से भी कम है। भारत जैसे बहुत ज्यादा श्रमिकों वाले देश में, ऐसे किसी विकल्प को नहीं चुना जा सकता है जिसकी वजह से रोजगार में कमी आए।

थाईलैंड में, 3 विदेशी विक्रेताओं ने मात्र 13 सालों में बाजार के 38 प्रतिशत हिस्से में कब्जा कर लिया है। इसकी तुलना इस तथ्य के साथ कीजिये कि पश्चिम में इस प्रकार के बाजार नियंत्रण में 60–80 साल लगते हैं। थाईलैंड में दसों हजार स्थानीय दुकानदारों का सफाया हो गया। ऐसा अनुमान है कि पिछले 10 सालों में 30 प्रतिशत से ज्यादा स्वतंत्र छोटे विक्रेता खत्म हुए हैं।

यू.एस.ए. में खाने पर खर्च किये गये प्रत्येक डॉलर पर, किसानों को मात्र लगभग 19 सेन्ट प्राप्त होते हैं। पांच साल पहले, उन्हें लगभग 40 सेन्ट प्राप्त होते थे। यू.एस. के किसानों को फार्मगेट मूल्यों के रूप में क्या मिलता है, विभिन्न उत्पादों के लिये 7 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अंतिम फुटकर मूल्य का अनुपात। भारत में, उत्पादों के विभिन्न आकलनों के अनुसार वर्तमान में किसान 50 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक प्राप्त कर रहे हैं। इस बीच, ओ.ई.सी.डी. किसानों को 2009 में अपनी सरकारों से 1260 बिलियन डॉलर की एक कृषि अनुदान प्राप्त हुआ, अतः व्यापार का यह ढ़ांचा किसानों का समर्थन नहीं करता है।

बड़े विदेशी परचून उत्पादों के वैश्विक स्रोत पर गुजारा करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बड़े विक्रेता कोई नया बाजार नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि बाजार में मौजूद विक्रेताओं का ही स्थान लेने वाले हैं। हमारे विक्रेता और व्यापारी विश्व में सबसे कम मूल्य और लाभ के साथ काम करते हैं। इसी से यह समझ लेना चाहिये कि फुटकर मूल्यों का ज्यादातर प्रतिशत किसानों के पास जाता है और यह भी कि उपभोक्ताओं के लिये कीमतें भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं।

ऐसा कहा जाता है कि चीन को वॉलमार्ट जैसे बड़े विदेशी विक्रेताओं से लाभ मिला है। चीन ने अकेले 2010 में यू.एस.ए. के साथ 265 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष किया है। वॉलमार्ट चीन का अकेला सबसे बड़ा खरीदार है। चीन के दोष की तुलना में भारत में वार्षिक माल व्यापार में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का घाटा है। चीन के साथ वार्षिक व्यापार का घाटा, जो अभी 20 बिलियन डॉलर है, और भी बुरा हो सकता है यदि बड़े विदेशी विक्रेता चीनी अधिशेषों का सफाया कर और उन्हें भारत में बेचकर, भारतीय सामानों के मूल्यों का निर्धारण करेंगे/उन पर खतरा बनेंगे।

^NkV fdlkuk dk cgrj Qk;nk% lcr rk fdlh vkj fn'kk e bfxr djr g!*

यह बताया गया है कि विक्रेताओं को अपने ज्यादातर उत्पाद 10 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 'छोटे किसानों' से लेने होंगे। आई.आई.एम. अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह के अनुसार, 'भारत की घरेलू ताजा खाद्य सुपरमार्केट का प्रचालन और उपभोक्ताओं के रुपयों में उत्पादक के साझे में कुछ खास अंतर नहीं है, उत्पादकों की मार्केटिंग की लागत को कम करने के अतिरिक्त।' वे आगे यह भी बताते हैं कि 10 हेक्टेयर की सीमा छोटे किसानों के लिये किसी काम की नहीं है क्योंकि केवल 1 प्रतिशत भारतीय किसानों के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है और फुटकर बाजार में एफ.डी. आई. को लाने को उचित ठहराने के लिये इसका उपयोग किया जाना कोई वैध तर्क नहीं हो सकता है। यह भी दस्तावेजीकृत किया जा रहा है कि यातायात के मूल्यों को कम करने के लिये भारत में कृषि परियोजनाओं को अनुबंध करने की स्थिति में, औद्योगिक इकाईयां कुछ बड़े उत्पादकों के साथ काम करना बंद कर देंगी। यह भी अनुभव किया गया है कि कृषि अनुबंधों के इकरार करने के लिये तृतीय पक्ष के रूप में सरकारी इकाईयों की मौजूदगी के साथ, त्रिपक्षीय करारों ने भी हमेशा किसानों के हितों की रक्षा नहीं की है (पंजाब के चावल निर्माताओं ने काफी घाटा सहा क्योंकि ठेकेदारों ने करार की शर्तों को पूरा नहीं किया, जबकि सरकार भी करार का एक पक्ष थी)। किसी अन्य स्थान से भी प्राप्त अनुभव (जैसे यू.के. में टेस्को) यह दर्शाते हैं कि ये विक्रेता छोटे किसानों का शोषण करते हैं, उत्पादन तंत्र में अरक्षणीय परिवर्तन करते हैं और किसान के हाथों से नियंत्रण छीन लेते हैं जो सुपरमार्केट के अतार्किक मानकों के साथ नामंजूरी का जोखिम उठाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि बड़े विदेशी फुटकर विक्रेता वैश्विक स्रोतों से भी साधन जुटायेगा (वितरण श्रृंखला में जहां से दिया गया उत्पाद सस्ता होगा) और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार किस प्रकार से इन इकाईयों द्वारा भारत में लघुधारकों से खरीद करने और उन्हें उचित मूल्य देने की गारंटी प्रदान करने की योजना बना रही है। यू.एस.ए. जैसे देशों से प्राप्त आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि एक औसत नागरिक द्वारा खर्च किये गये प्रत्येक खाद्य डॉलर का नियमित घटता हुआ प्रतिशत ही वहां के किसानों को मिला है और खेती को हमेशा ही सरकार से बढ़कर मिलने वाले अनुदानों से संभालने की आवश्यकता पड़ी है, जो अंततः नागरिकों पर एक सार्वजनिक वित्तीय बोझ के रूप में पड़ता है।

^,d djkM+ u;h jkstxkj & dgk vkSj fdl eqY; ij*

ऐसा अनुमान है कि भारत में औसत रूप से प्रत्येक 80 नागरिकों के लिये एक फुटकर विक्रेता है। खाद्य नीति विश्लेषक, देविंदर शर्मा भारतीय फुटकर बाजार को 400 बिलियन डॉलर का निर्धारित करते हैं, 120 मिलियन से ज्यादा फुटकर विक्रेताओं के साथ और 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर।

इसमें कॉर्पोरेट्स का साझा आनुमानित केवल 5 प्रतिशत है, जबकि 95 प्रतिशत बाजार पारंपरिक फुटकर विक्रेताओं द्वारा संभाला जाता है। इसकी तुलना में, फुटकर श्रृंखला में वैश्विक सुपरमार्केट के प्रवेश के साथ निर्मित होने वाली 1 करोड़ नौकरियां (या यह केवल 20 लाख है?) नगण्य लगती हैं! आधार रेखा में यह प्रतीत होता है कि 400 मिलियन लोगों को हटाया जाना है और 1 करोड़ (लम्बी चौड़ी हांककर) लोगों को रोजगार दिया जाना है।

यकीनन, यह मानवता के इतिहास में किसी भी क्षेत्र में हुआ सबसे बड़ा प्रतिस्थापन है जो भारतीय कृषि में प्रकट हो रहा है, जिसमें कृषि और हमारे गांवों से लाखों ग्रामीण जनसाधारण को दूर जाना होगा। कृषि के लिये निर्मित हुआ शत्रुतापूर्ण वातावरण और भी ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि अन्य क्षेत्र इनके एक खंड को भी अपनाने में सक्षम नहीं हैं। बड़े विदेशी फुटकर विक्रेता वर्तमान मंदी का उत्तर नहीं हैं बल्कि स्थिति को और भी बिगाड़ेंगे।

fdlku vkSj NksVs foØsrk miHkksDrk Hkh gSa---& mudh [kk|@iks"k.k lqj{kk dks tksf[ke esa Mky nsuk

प्रत्यक्ष और स्पष्ट 'नगरीय' उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में, विदेशी निवेश और फुटकर में कंपनियों को लाने के कदम ग्रामीण उपभोक्ताओं से संपर्क करते लगते हैं – विशेषरूप से किसान और छोटे फुटकर विक्रेता (अनौपचारिक क्षेत्र सहित जो भारत की 93 प्रतिशत जनता को अब भी रोजगार देता है) जिनकी गणना वाकई सरकार की आंखों ने नहीं की है।

ग्रामीण भारत में पोषण का सेवन साल दर साल में नीचे आता रहा है। विडम्बना यह है कि सबसे ज्यादा भूखे भारतीय ग्रामीण भारत में ही है, जो हमारे खाद्य उत्पादन में सम्मिलित होते हैं। वर्तमान परिदृश्य में कृषि उत्पादन की कीमतें किसानों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिससे यह ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था संपूर्ण निर्धनता की ओर अग्रसर हो रही है; बड़े विदेशी फुटकर विक्रेता देश के सबसे गरीब क्षेत्रों में स्थिति लघुधारकों से साधन लेने की संभावना नहीं है। किसी भी अन्य स्थान से आने वाले सस्ते उत्पाद भारत में वर्तमान फुटकर संरचना के माध्यम से हमारे उत्पादकों के लिये मौजूद मामूली अवसरों को भी दूर ले जाएंगे।

वर्तमान आंकड़े यह इंगित करते हैं कि नगरीय उपभोक्ताओं की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ता कम फल, सब्जियां और ताजा दूध लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की पोषण सुरक्षा का ध्यान रखने और इस प्रचलन को संतुलित करने के लिये अब तक सरकार के किसी भी विभाग पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है (पी.डी.एस. को छोड़कर जिसे विखंडन के लिये प्रस्तावित किया जा रहा है और 'प्रत्यक्ष रकम स्थानांतरण' तंत्र से प्रतिस्थापित किया गया है)।

^cSd&,saM volajpuk esa fuos'k & D;k ;g tukns'k vkSj ykxw gks ldrk gS*

विकास की आवश्यकता के कारण के रूप में फसल के बाद के नुकसानों का हवाला दिया गया है, जिसे अनिश्चित और अस्पष्ट रूप से 'बैक–एंड अवसंचरना' के रूप में पारिभाषित किया गया है; उद्देश्य की धाराओं में से एक यह है कि एफ.डी.आई. के निवेश में से 50 प्रतिशत बैक–एंड अवसंरचना पर लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि, पूंजी खर्च करने का ऐसा पृथक्ककरण मापन के लिये प्रायोगिक नहीं है और यही वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इसके बाद इसे स्व–विनियमन के लिये छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार का प्रस्ताव और इसकी वृहद असफलता जी.एम. खाद्य में उद्योगों द्वारा किये गये स्व–विनियमन और ऐच्छिक घोषणा में पाये गये थे! बड़ी फुटकर श्रृंखलाओं के पिछले व्यवहार और वैश्विक प्रतिरोध ऐसे लचीले नियामक शासन को सही साबित नहीं करते और विशेष रूप से तब जब उनके भाग का यह 50 प्रतिशत निवेश प्रथम स्थान के फुटकर में एफ.डी.आई. को सही ठहराने के लिये सरकार द्वारा बार–बार उपयोग में लाया जा रहा हो। हमारे पास ऐसे किसी भी निवेश का प्रबंधन करने या इसे सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान में कोई भी नियंत्रक प्रणाली या संचालन तंत्र नहीं है।

यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार की अवसंरचना के संदर्भ में कहा जा रहा है, उसके मूल्य का कुछ भी भारतीय भीतरीप्रदेश के लोगों लिये नहीं जोड़ा जाएगा। यह विश्वस्त हैं कि ये कम्पनियां किसी ढ़ांचे की स्थापना या विमोहित क्षमता पर निवेश या ऐसी किसी अवसंरचना पर कुछ नहीं करने वाली बल्कि इससे आंशिक रूप से कार्य कर रहे तंत्र पर ही बोझ बढ़ेगा। यह अस्वाभाविक है कि वितरण श्रृंखला की अवसंरचना पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। यदि ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन किया जाए और उससे प्राप्त परिणाम चाहे कुछ भी हो, वे हमारे लघुधारकों या उनके लिये आवश्यक अवसंरचना को

उन्नत नहीं कर पाएंगे। हमारी 94 प्रतिशत सड़कें जिलों और गांवों में हैं। ऊर्जा की कमी अभी भी है और आगे भी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप उदासीन श्रृंखला अवसंरचना प्रभावित होंगी। असल में, बड़े विदेशी फुटकर विक्रेता आर्थिक रूप से अमित्रवत और ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग करने वाले हैं। विदेशी फुटकर विक्रेता इन मुद्दों से कैसे निपट सकते हैं?

D;k cMh QVdj J`[kyk;sa LFkkuh; vFkZO;oLFkk vkSj xjhch de djus esa lg;kx djsxh ;k doy blds vkxs viuk eukQk ns[ksxh

बड़ी फुटकर श्रृंखलायें किसानों की गरीबी को कम करने या उन्हें बेहतर मुनाफा देने में सहयोग देती तो नहीं लगती हैं। पूरी दुनिया में किये गये कुछ अध्ययन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। यू.एस. में किये गये एक अध्ययन में यह पाया गया है कि वॉलमार्ट की उपस्थिति से उस क्षेत्र के समुदायों में गरीबी बढ़ी है। ऐसा अनुमान है कि यू.एस.ए. में (2005 में) लगभग 20 हजार लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। लेकिन, अधिक महत्वपूर्ण बात, इस अध्ययन के लेखक ने एक चेतावनी दी है जो हमारे समुदाय के लिये बर्बादी की तरह लगती है; अपने निष्कर्ष में, उन्होंने कहा, ''उद्यमियों के स्थानीय वर्ग को प्रतिस्थापित करके, वॉलमार्ट श्रृंखला स्थानी प्रतिनिधित्व की क्षमता को भी खत्म करती है।'' यहां यह ध्यान देना उचित होगा कि वॉलमार्ट के मात्र 1.2 प्रतिशत कर्मचारी ही यहां की सरकार की गरीबी रेखा से ऊपर हैं। वॉलमार्ट ने बहुत संदेहास्पद श्रम अभ्यासों के साथ कर्मचारियों के नाम पर एक बहुत अनैतिक बीमा 'मृत किसान बीमा' तक करवाया हुआ है जो है तो कर्मचारियों के नाम पर लेकिन उसका फायदा कम्पनी को होगा।

इसी प्रकार से, एक अन्य बड़ी फुटकर विक्रेता जिसका नाम भी अक्सर लिया जाता रहा है, टेस्को, ने भी समुदायों और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है; एक रिपोर्ट यह बताती है कि टेस्को यू.के. के किसानों को 'दिवालियापन की कगार पर' पर ढकेल रहा है। लघु एवं पारिवारिक कृषि संधि के चेयरमेन, माइकल हार्ट के अनुसारः ''टेस्को मांस, सब्जियों, सबकुछ की कीमते नीचे ला रहा है, क्योंकि बाजार में सबसे शेयर बहुत ज्यादा है। यह एकाधिकार की स्थिति है.... वे आगे जा सकते हैं और किसी ऐसे को खोज सकते हैं जो उनकी इच्छा की कीमतों पर उन्हें माल वितरित कर सके।'' एक न्यूज रिपोर्ट ने फुटकर श्रृंखलाओं को माल देने का काम करने वाले किसानों की स्थिति को ''उधार के बंधुआ मजदूर'' कहा है।

यू.के. में सुपर मार्केट श्रृंखलाओं के व्यापार अभ्यासों के विरोध की गई कई शिकायतों का निरीक्षण करके किया गया एक विस्तृत अध्ययन कहता है, ''कीमतों की कार्यप्रणाली के मद्देनजर.... हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि..... प्रतिस्पर्धा को विकृत किया गया और जटिल एकाधिकार स्थिति का निर्माण किया गया... और...सार्वजनिक हितों के विरुद्ध काम भी किया गया।''

वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई विकासशील देशें में स्थानीय फुटकर विक्रेताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को पहले ही देखा गया है (जहां विदेशी फुटकर श्रृंखलाओं को अनुमति देने के 4 साल के भीतर ही 14 प्रतिशत स्थानीय फुटकर विक्रेताओ ने अपना काम बंद कर दिया) और भारत में, बड़ी घरेलू फुटकर श्रृंखलायें पहले से ही स्थानीय खिलाड़ियों को व्यापार से बाहर का रास्ता दिखाया है। एक अर्थशास्त्री यह बताते हैं कि बैंगलोर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में 33–60 प्रतिशत पारंपरिक फल और सब्जी फुटकर विक्रेताओं ने 15–30 प्रतिशत ग्राहकी में कमी, 10–30 प्रतिशत से बिक्री में कमी और 20–30 प्रतिशत आय में कमी बताई है।

mRiknd dh vifjorZuh; {kfr & miHkkDrk lc/k

चूंकि इस तथाकथित 'फुटकर क्रांति' के आगमन में भूदृश्यों पर हावी कई घरेलू फुटकर श्रृंखलायें शामिल हैं, इसलिये खाद्य सामग्रियों के उत्पादक के रूप में किसान और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी भी काफी बढ़ गई है। इसका अर्थ है उपभोक्ता पर 'सुरक्षित खाने' और किसान का उपभोक्ता के लिये 'परवाह' करने के किसी भी सुझाव का प्रतिस्थापित होना। प्रारंभिक 'हरित क्रांति' ने पर्यावरण, स्वास्थ्य और विविधता के मूल्य पर ज्यादा धन की प्राप्ति के लिये पर्यावरण–माननाशक, महंगे रासायनिक निवेश की सहायता से बड़े पैमाने पर एकधान्य कृषि का प्रचार किया था। बाद के त्वरित प्रभावी तकनीकी–उलझनें जैसे जी.एम. बीज इसी परिप्रेक्ष्य का खराब रूप ही है। इस देश में किसानों की और ज्यादा आत्महत्याओं का पथ निरंतर स्थिरता के साथ तैयार किया जा रहा है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इस देश में पारंपरिक फुटकर विक्रेताओं का उनके ग्राहकों के साथ एक मूलभूत संबंध है। कई फुटकर विक्रेताओं की ओर इस देश में गरीबों के लिये उधार (उधार पर सामान) भी मौजूद रहता है जो बड़े फुटकर विक्रेताओं के पास नहीं मिलता। पारंपरिक फुटकर विक्रेताओं की स्थिति में उपभोक्ताओं की निकटता भौतिकीय निकटता भी है। इसी बीच, भारत में उपभोक्ताओं की एक पीढ़ी (महानगरों में फुटकर श्रृंखलाओं के आ जाने के बाद से) किसानों और कृषि से किसी भी प्रकार के जुड़ाव को खो चुकी है क्योंकि उनके पास ज्ञात या पड़ोसी विक्रेता थे। इस प्रकार की अनभिज्ञता का परिणाम कम कीमत, पोषक, स्व–घोषित 'वैल्यू ऐडेड' पोषक खाद्य सामग्री के साथ स्थानीय खाद्य सामग्रियों का प्रतिस्थापन है, जो परिवार के बजट को डगमगा देता है और प्रायः बहुत ज्यादा स्वास्थ्यकर खाद्य समाधान भी नहीं होता है। जबकि बड़ी फुटकर श्रृंखलाओं के अपक्षयी रोगों और विस्तार के विस्फोट को सहसंबंधित करने के लिये कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया है, ऐसा पिछले 10 सालों में तथाकथित 'फुटकर क्रांति' के दौरान उसी समय पर हुआ है। दुनिया के दूसरे भागों में, सुपरमार्केट्स की वृद्धि ने नकारात्मक प्रभाव छोड़े हैं, जिसमें 'खाद्य क्षेत्र का केन्द्रीकरण, विशेष रूप से ताजा उत्पादनों में, विशेषज्ञों की बहुत कमी और स्थानीय प्रादेशिक उत्पादनों की उपलब्धता में कमी' सम्मिलित है।

vR;f/kd miHkkDrk dkcZu infpUg cukuk

सतत कृषि व्यवसायी ज्यादा बड़े पर्यावरणीय दृश्य का साझा करते हैं जहां विश्व खाद्य पदार्थों का उसके स्रोत से कम दूरी तक यातायात करके साथ ही साथ कृषि में पेट्रोलियम आधारित रासायनों का उपयोग कम से कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। खाद्य सामग्रियों को ज्यादा दूर तक ले जाने से भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रति इकाई उपभोग कार्बन पदचिन्ह भी बढ़ता है। यह अनुमान है कि फुटकर सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थ यू.एस.ए. में अलमारियों तक आने से पहले 1500 खाद्य मीलों का सफ करते हैं। यह सवाभाविक है कि ये सस्ते उत्पादों के लिये विश्व संसाधनों के साथ बहुत कुछ करते हैं और इनके लिये कार्य पर उच्च गुणवत्ता और अन्य मापदंड आवश्यक नहीं है। भारत, इस साल की शुरूआत में, विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश था, जो आखिरकार एक संदग्धि गौरव बन गया है। बड़े विदेशी फुटकर विक्रेता केवल कार्बन पदचिन्ह बढ़ायेंगे।

cM+s [kqnjk dh ek/;e ls vkuqokaf'kd :i ls la'kksf/kr [kk| inkFkksa dk ?kqliB

कहीं और, केन्द्रीकृत, एकाधिकार बाजार के अंदर स्थित करने के लिये पृथक्करण और सरूपता संरक्षण प्रणाली के लिये, सूचित विकल्पों पर उपभोक्ता के अधिकार और उनके खाने में मौजूद अवयवों के बारे

में जानने के अधिकार को संरक्षित करना उपभोक्ताओं का दबाव है। जी.एम. फूड्स की स्थिति में यह और भी ज्यादा लागू होता है जहां लेबल लगाने का काम कई देशों में ही किया जाता है ताकि सूचित विकल्पा के उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन न हो। यह भी अस्वाभाविक है कि जहां सूचित बहस लेबल लगाने जैसे अधिनियमों के साथ जुड़ती है, वहां अनचाहे, अनैच्छिक खाद्य पदार्थों को जबरदस्त तरीके से अस्वीकार किया जा रहा है जैसे जी.एम. फूड्स। भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्त से संबंधित सूचना बहस की कमी, और प्रभावी तथा वहनीय उपभोक्ता सुधार तंत्र की नामौजूदगी का ध्यान रखते हुए, फुटकर में एफ.डी.आई. का शुरू होना भारतीय बाजार में तैयार रूप में जी.एम. सामग्रियों के बढ़ते घुसपैठ का कारण हो सकता है। यह विशेषरूप से कहीं और जी.एम. खाद्य सामग्रियों की बढ़ती अस्वीकृति को दिया गया है।

ge] vkशkk e] bl fu.k; ij igp g fd%

कहीं से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह बताए कि बड़े विदेशी खुदरा स्थानीय किसानों या उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक होंगे; या रोजगार के मौकों में वृद्धि करेंगे; या बहिर्गमन को बाधित करके निवेश को देश में ही रखेंगे;

भारतीय स्थिति वर्तमान खुदरा संरचना (जैसे कृषि उत्पादन, फुटकर बिक्री भी यहां पारंपरिक रूप से समुदाय का मामला है) की सकारात्मक संभावनाओं की अच्छी वृद्धि का विश्वास दिलाती है ओर इन वितरण श्रृंखलाओं में कोई भी अक्षमता, या अवसंचरना में कमी को अन्य तरीकों से सरकार द्वारा संबोधित किया जाना है क्योंकि एफ.डी.आई. के प्रस्तावों में इसे सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं है;

खाद्य सामग्रियों की महंगाई का सामना भी अन्य साधनों से करना है, और फुटकर में एफ.डी.आई. में इस समस्या के लिये विध्वंसकारी गलत साधनों का निर्माण नहीं किया जा सकता है;

यह कि ऐसे नीति प्रस्ताव असल में किसानों सहित लाखों आजीविकाओं को बर्बाद कर देंगे और एकाधिकार का निर्माण करेंगे (बड़े विदेशी फुटकर विक्रेताओं के साथ मुनाफे का साझा करके कृषि–इनपुट कम्पनियों और व्यापारिक कम्पनियों को शामिल करके), किसानों और उपभोक्ताओं के लिये बहुत कम विकल्प और उनके हाथों में बहुत कम नियंत्रण छोड़ेंगे;

यह कि इससे असतत उत्पादन और उपभोग रीतियां बढ़ेंगे जो भारत में विकल्पों की उपलब्धता को पूर्णतः बेकार कर देंगे। vkशkk ljdkj }kjk ,lh dkb Hkh uhfr pykus d fojk/k e gA